(Interruptions) Please sit down. *(Interruptions)* Please sit down.... *(Interruptions)*.. I have said, "Please sit down."... *(Interruptions)*... Nothing is going on record except what I am announcing: ... *(Interruptions)* ...

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held on Thursday, the 5th December, 1996 allotted time for Government Legislative Business as follows:

(1) Consideration and return of the Income Tax (Amendment) Bill, 1996, as passed by Lok Sabha. It may be disposed of without discussion because there is nothing to be discussed in this matter. ... *(Interruptions)* ... It is in relation to Andhra cyclone. We are giving some consideration to that That is why I am saying this. There cannot be two opinions on this. We have to support the cyclone affected people of Andhra.

(2) Consideration and passing of the Companies (Amendment) Bill, 1996.— 2 hours.

(3) Consideration and passing of the Delhi Development (Amendment) Bill, 1996, after it has been passed by Lok Sabha- 2 hours.

(4) Consideration and passing of the Constitution (Eightieth Amendment) Bill, 1996, after it has been passed by Lok Sabha.--4 hours.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, I have to make a point in regard to this Business. ... *(Interruptions)* ... Madam, the Government is not informing the House about its intentions on the Insurance Bill. Everything is being said outside. Madam, you must have seen today's newspapers; there is even a news item that the Government is insistent that this Bill should be passed in this Session. But we are not being informed. 1 would like to request that the Government , should not take the House by surprise. If they want to introduce it, they should make their intentions clear. ... *(Interruptions)* ....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am asking the Minister of Parliamentary Affairs to announce Government Business.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): लोकपाल बिल के बारे में कुछ नहीं है। इस सत्र के नौ दिन बाकी हैं, लोकपाल बिल आ रहा है या नहीं आ रहा?

THE DEPUTY CHAIRMAN: One more Member has also sought a clarification on this. I will look into it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Madam, I will convey the direction given by the Chair to the concerned Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, you make statement on Government Business.

ANNOUNCEMENT RE: GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 9TH DECEMBER, 1996

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 9th December, 1996 will consist of:

1. Consideration and return of the Income-Tax (Amendment) Bill, 1996 as passed by Lok Sabha.
2. Consideration and passing of:
   a) The Companies (Amendment) Bill, 1996.
   b) The Provisions of Panchayats (Extension to Schedule Areas) Bill, 1996.
   c) The Coal India (Regulation of Transfers and Validation) BilI, 199S.
3. Consideration and passing of the following Bills as passed by Lok Sabha:
   a) The Delhi Development (Amendment) Bill 1996.

b) The Constitution (Eightieth Amendment) Bill, 1996.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I would like to know whether the Government is really interested in the Insurance Bill. ... *(Interruptions)* ...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: लोकपाल बिल की क्या पोजीशन है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will find out. ... *(Interruptions)* ...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): मैडम डिप्टी चेयरमेन, मैं भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनका जिक्र बाहर हो रहा है, जैसे इन्शोरेन्स बिल है और लोकपाल बिल का कभी हम सुनते है कि आ रहा है, कभी सुनते हैं कि नहीं आ पा रहा है। इसी तरह से यह कहा जाता है कि चीफ जस्टिस एनाउन्स है, उसका नाम भी ले दिया जाता है बिना प्रक्रिया पूरी किए हुए। वह यहां हमको क्यों नहीं बताया जाता? इसके साथ-साथ यह भी बाहर अखबारों में निकलता है कि जुडिशियरी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अभी बहुत से अपने बिल सरकार ला रही है। यह इस तरह की सब बातें बाहर की जाती हैं, लीकआऊट सरकार की तरफ से की जाती हैं। हमको, सदन को क्यों नहीं इसके बारे में कॉन्फीडेन्स में लिया जाता? पारदर्शिता की अगर बात है तो हमें कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए कि आप किसको चीफ जस्टिस बनाने वाले हैं। आप यहां एनाउन्स करिए। अगर आप कोई बिल लाना चाहते हैं एम॰पीज॰ को करप्शन एक्ट से हटाने के लिए, तो उस बारे में हमको बताइए और यहां पर घोषण करिए।

यह तरह-तरह की जो बाहर बातें की जाती हैं, जो नियम और पॉलिसी के संबंध में है, यहां पर इतने सदस्य है, किसी को भी इनके बारें में मालूम नही है।

उपसभापति: आपने इन सब बिलों की बात करी, मगर आपने महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन के बिल की बात नहीं करी, बड़े अफसोस की बात है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैडम, मैं क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि वह भी एक अति-आवश्यक बिल था, उसके संबंध में भी सबको अंधेरे में रखा गया है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे (महाराष्ट्र): वह आ रहा है।

उपसभापति: क्योंकि आपको फिकर है लोकपाल बिल की, किसी को फिकर है इंश्योरेंस की, मगर जो महिलाओं को आप सब पार्टीज़ ने मिलकर 12 मार्च को एक इंश्योरेंस दी थी और एश्योरेंस दी थी, उस ऐश्योरेंस की क्या इंश्योरेंस है वह कोई नहीं बोल रहा, न आप अंदर बोल रहे हैं और न बाहर बोल रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उस बिल को लाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, हम सब तो उसका समर्थन कर रहे हैं।

उपसभापति: आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, यही तो मुझे शिकायत है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: एजेंडा में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे?

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: इसलिए हम नहीं बोले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वह डेफिनेट्ली आ रहा है।

उपसभापति: यादव जी ने यह बात कही है कि क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत है, आप लोगों को भरना पड़ेगा यहां पर, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं और मुझे बोलना पड़ा।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट के बारे में भी कभी कहा जाता है कि हटाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि नहीं हटाया जाएगा। क्या होगा। इसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए? आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट के बारे में भारत सरकार की दृष्टि क्या है?

उपसभापति: अभी मुझे जो नाम लिस्टिड हैं, उनको बुलाना है, काफी समय निकल गया है। How can I finish. मंत्री जी, जो बोला जा रहा है, सब का जवाब दीजिएगा। लास्ट में जो मैंने बोला है, उसका पहले जवाब दीजिएगा। डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसाद।

RE. NEW RAILWAY LINES IN ANDHRA PRADESH

डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं आंध्र प्रदेश से संबंधित एक विशेष विषय की ओर आपके माध्यम से इस माननीय सदन का और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

The rail track along the coastline of Andhra Pradesh is generally swept away by cyclonic floods, almost every year disturhing all train services. Consequently, the economy of the